अन्नासाहेब बापूसाहेब पाटिल व अन्य

बनाम

बलवन्त उर्फ बालासाहेब बाबूसाहेब पाटिल (मृतक)

द्वारा विधिक प्रतिनिधि व वारिस आदि

जनवरी 6, 1995

[न्यायाधिपति के.रामास्वामी, एस. मोहन व एन. वेंकटचेलैय्या]

हिंदू कानून, हिंदू संयुक्त परिवार- ज्येष्ठाधिकार- अविभाज्य संपत्ति- उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार का नियम- यह स्थापित करने के लिए कि एक परिवार संयुक्त नहीं रह जाता है, कनिष्ठ सदस्यों की ओर से संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार को त्यागने के इरादे को साबित करना आवश्यक है।

हिंदू कानून- हिंदू संयुक्त परिवार-- अविभाज्य संपत्ति-वतन भूमि- महाराष्ट्र राजस्व पटेल (कार्यालय का उन्मूलन) अधिनियम, 1962 द्वारा दिनांक 01.01.1963 को 'पटेल वतन' का उन्मूलन- धारा 5 के तहत पुनर्ग्रहण- क्या पुन: अनुदान पर, जुड़ी वतन भूमि ने वतनदार की स्व-

अर्जित संपत्ति का स्वरूप ग्रहण कर लिया- नहीं- वतनदार को भूमि का पुन: अनुदान पूरे संयुक्त हिंदू परिवार के लाभ को सुनिश्चित करना चाहिए- परिवार के सदस्यों का विभाजन का दावा करने का अधिकार।

परिसीमा अधिनियम, 1963- अनुच्छेद 65- प्रतिकूल कब्जा- साक्ष्य का दायित्व- हिन्दू संयुक्त परिवार- वैधानिक अवधि के दौरान शत्रुतापूर्ण कथन।

अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी बी के पिता की 1956 में मृत्यु हो गई। बी स्वयं और अपीलकर्ता के संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा पुरुष सदस्य था। 'पटेल वतन' से जुड़ी कृषि भूमि की दो वस्तुओं को छोड़कर सभी संपत्तियों को माप और सीमा द्वारा विभाजित किया गया था। ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार, पटेल के कार्यालय से जुड़ी वतन संपत्तियाँ निष्प्रभावी हो गईं। महाराष्ट्र राजस्व पटेल(कार्यालय का उन्मूलन) अधिनियम, 1962 1 जनवरी, 1963 को लागू हुआ। पटेल वतन समाप्त हो गए।

बी. परिवार के सबसे बड़े सदस्य होने के नाते, अधिनियम की धारा 5 के तहत पुनः अनुदान प्राप्त किया, जो अधिभोग मूल्य के भुगतान पर पुनः अनुदान का प्रावधान करता है। अपीलकर्ताओं ने विभाजन और उसमें आधे हिस्से के आवंटन के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने दावे को डिक्री किया। हालाँकि, अपील में डिक्री को रद्द कर दिया गया था। उच्च

न्यायालय ने माना कि पुनः अनुदान के बाद, संपत्तियाँ बी की निजी संपत्ति बन गईं और इसलिए वे विभाजन योग्य नहीं थी। अपील में उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि 1965 में 'पटेल वतन' के ए.बी.पाटिल ब. बलवंत उन्मूलन और बी के पक्ष में पुनः अनुदान के परिणामस्वरूप, वतन के उन्मूलन और कार्यालय से जुड़े सेवा के भार के परिणामस्वरूप, पूर्व- भूमि से संबंधित मौजूदा अधिकार और देनदारियां समाप्त कर दी गईं और भूमि प्राप्तकर्ता और इसमें मौजूद शर्तों ने पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित किया। चूँकि यह वतनदार को व्यक्तिगत रूप से दिया गया पुनः अनुदान था, इसलिए संपत्ति उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति बन गई।

उन्होंने आगे कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागू होने के बाद, संपत्ति सनद के अनुसार स्व-अर्जित संपत्ति बन गई थी और बी भू-राजस्व के भुगतान के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार था। चूंकि कोल्हापुर जिले में वतनदारी अधिकारों की एक विशिष्ट विशेषता थी, इसलिए अनुदान से वतन के अस्तित्व का पता लगाना आवश्यक था और इसे अधिनियम की धारा 3 के संचालन के अधीन नहीं किया गया था। 1956 में दोनों पक्षों के निधन पर, पिता के उत्तराधिकार का अधिकार ज्येष्ठाधिकार के कानून के तहत खुल गया। रूढ़ि के अनुसार, परिवार के कनिष्ठ सदस्यों को संपत्ति में किसी भी हिस्से का अधिकार नहीं था। वर्ष

1956 में संपत्ति बी में निहित हो गई और केवल उसके उत्तराधिकारी ही बी की संपत्ति के उत्तराधिकारी थे। इसलिए, अपीलकर्ताओं को संपत्ति में किसी भी विभाजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था।

संबंधित अपील विलास जी. देवी बनाम रामचन्द्र वाई. दलवी और अन्य में, यह भी तर्क दिया गया कि उत्तरदाताओं ने नुस्खे द्वारा स्वामित्व प्राप्त किया था। यह कथन भी किया गया है कि उत्परिवर्तन 16 अगस्त, 1955 को प्रभावी हुआ था और उस तिथि से उत्तरदाता अनन्य कब्जे और उपभोग में थे और वतन के उन्मूलन और उसके बाद के पुनर्ग्रहण के बाद यह उनकी अनन्य संपत्ति थी, जिस पर उन्होंने प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व प्राप्त किया था।

क्या अधिनियम कि धारा 5 (1) के तहत पुनः अनुदान से जुड़ी वतन भुमि ने वतनदार की स्वयं अर्जित संपत्ति का स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह विचार के लिए उठाया गया प्रश्न था।

इस न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि

1:1. ज्येष्ठाधिकार का अर्थ, पहले जन्म और उम्र में वरिष्ठतम के अपने छोटे भाई को वरीयता देते हुए संपत्ति में उत्तराधिकार पाने का अधिमान्य अधिकार है। अविभाज्य संपत्ति में हालांकि अन्य अधिकार जो

एक सहदायिक को संयुक्त परिवार की संपत्ति में जन्म से प्राप्त होते हैं, मौजूद नहीं हैं, वरिष्ठ सदस्य के जन्म के समय उत्तरजीविता द्वारा प्राप्त करने का अधिकार अभी भी बना हुआ है। यह स्थापित करने के लिए कि मिताक्षरा द्वारा शासित एक परिवार जिसमें एक अविभाज्य संपत्ति संयुक्त नहीं रह गई है, परिवार के कनिष्ठ सदस्यों की ओर से अपने अधिकार को त्यागने के इरादे को साबित करना आवश्यक है। केवल भोजन और निवास में पृथककरण दर्शाना पर्याप्त नहीं है। रूढ़ि या विशेष कानून हिंदू संयुक्त परिवार के जीवित रहने से उत्तराधिकार के नियम को विस्थापित करता है। [95-एफ-जी]

दत्तात्रेय और अन्य बनाम कृष्णा राव और अन्य, [1993] समर्थन। 1 एससीसी 32, पर आश्रय किया।

1.2 धारा 3 महाराष्ट्र राजस्व पटेल (कार्यालय का उन्मूलन) अधिनियम, 1962 के संचालन ने 3, वतन को समाप्त कर दिया गया है और वतनदारी से जुड़े सभी वृतांत जिसमें पहले से मौजूद प्रथा, कानून का प्रवर्तन या अदालत की कोई डिक्री या आदेश शामिल हैं, को रद्द कर दिया गया है। इसलिए, वतन से जुड़े वृतांत यानी पटेल के रूप में सेवा प्रदान करने का दायित्व विलुप्त हो गया और भूमि रैयतवारी भूमि बन गई, वतन का कार्यालय समाप्त हो गया, वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार समाप्त हो गया और पुनः अनुदान पर भूमि हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति बन गई जो

संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के लिए और उनकी ओर से वतनदार के पास थी परिवार के सभी सदस्य जीवित रहने पर विभाजन के अधिकार का दावा करने के हकदार बन गए। यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1953 के बाद 1 जनवरी, 1963 को लागू हुआ था इसलिए, 1956 में पिता की मृत्यु के बाद, वतनदार के रूप में उत्तराधिकार का अधिकार मौजूदा वतन कानून के अनुसार वरिष्ठ वंशीय पुरुष वंशज के लिए खुल गया। पुनः अनुदान 1965 में दिया गया, जिस वर्ष परिवार के सभी सदस्यों को विभाजन का दावा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार, वादी सं. 1 अपने भाई के साथ 15 एकड़ 20 गुंठा में 1/2 हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार बन गया। [98-ई-एच]

1.3 वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को तब तक बाहर रखा गया जब तक कि सेवा के भार के साथ वतन को समाप्त नहीं कर दिया गया। पुनः अनुदान दिए जाने के बाद, संपत्ति सहदायिक हो गई और सहदायिकों के बीच विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। [99-एच, 100-ए]

2.1 जहां कब्जे को वैध स्वामित्व के लिए संदर्भित किया जा सकता है, वहां इसे प्रतिकूल नहीं माना जाएगा, इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति का कब्जा वैध हक के लिए संदर्भित किया जा सकता है, उसे यह दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसका कब्जा दूसरे के स्वामित्व के

प्रति शत्रुतापूर्ण था। जो व्यक्ति दूसरे की ओर से कब्ज़ा रखता है, वह केवल उस दूसरे के स्वामित्व से इनकार करके अपने कब्जे को प्रतिकूल नहीं बनाता है ताकि वह खुद को परिसीमा क़ानून का लाभ दे सके। इसलिए, जो व्यक्ति वैध स्वामित्व के साथ कब्ज़ा करता है, वह यह दिखावा करके कि उसके पास कोई स्वामीत्व नहीं है, वह उस स्वामीत्व से दूसरो को वंचित नहीं कर सकता है। (101-ए-बी]

2.2 हिंदू संयुक्त परिवार के मामले में, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के बीच हितों का समुदाय और कब्जे की एकता है और प्रत्येक सहदायिक सहदायिक संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व और उपभोग का हकदार है। केवल इस तथ्य का कि सहदायिकों में से एक के पास संयुक्त कब्ज़ा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बेदखल कर दिया गया है। परिवार के किसी सदस्य द्वारा पारिवारिक संपत्ति पर कब्ज़ा अन्य सदस्यों के प्रतिकूल नहीं हो सकता है, बल्कि उसे स्वयं और अन्य सदस्यों की ओर से माना जाना चाहिए। इसलिए, एक का कब्ज़ा सभी का कब्ज़ा है। प्रतिकूल कब्ज़ा स्थापित करने वाले सदस्य पर अपने कब्जे के प्रतिकूल स्वरूप को सकारात्मक रूप से साबित करने का भारी बोझ होता है कि अन्य सदस्यों की जानकारी में उसने अपने अनन्य स्वामित्व का दावा किया है और अन्य सदस्यों को संपत्ति का उपभोग लेने से पूरी तरह से बाहर रखा गया है और इस तरह का प्रतिकूल कब्ज़ा वैधानिक अवधि तक

जारी रहा। लगान और राजस्व की वसूली के लिए परिवार के बड़े भाई के नाम पर नामांतरण दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्य साबित नहीं होता है। [101-सी-ईजे]

2.3 वर्तमान मामले में, विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने का वादी का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उत्पन्न हुआ था और कलेक्टर द्वारा धारा धारा 5(1) के तहत पुनः अनुदान दिया गया था। इसलिए, प्रतिवादी को अभिवचन करना होगा और साबित करना होगा कि पुन: अनुदान के बाद, उसने वाद की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति पर अपना अनन्य अधिकार, हक और हित का दावा किया और वादी ने अधिकार के ऐसे शत्रुतापूर्ण उपयोग को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को 12 वर्षों की संपूर्ण वैधानिक अवधि के दौरान बिना किसी बाधा के उस शत्रुतापूर्ण हक के दावे में वर्णित संपत्ति का निरंतर कब्ज़ा और उपभोग लेने की अनुमति दी गई और वादी इस पर कायम रहा।

2.4 जब तक वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार के नियम के प्रचालन से भूमि की प्रकृत्ति बदली नहीं गई तब तक भूमि अविभाज्य थी और उसमें वादी विभाजन के लिए किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। अधिनियम लागू होने के बाद और पुनः अनुदान पर, विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए वाद कारण उत्पन्न हुआ था। [101-एच] जी

2.5 इस बात का कोई अभिवचन आैर सबूत नहीं था कि प्रतिवादियों ने वादी की जानकारी में संपत्ति पर अपने शत्रुतापूर्ण अधिकार का दावा किया था और वे इससे सहमत थे। इसके अभाव में विभाजन का दावा करने का अधिकार तभी उत्पन्न होगा जब विभाजन के अधिकार से इनकार कर दिया गया हो। अधिनियम के तहत भूमि के अविभाज्यता से भाज्यता के स्वरूप में बदल दिया गया था,और दोनों अदालतों ने यह सही माना था कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व प्राप्त नहीं किया है। [102-ए-बी]

दिवानी अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नं. 32/1980

बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रकरण सं. 162/1969 में निर्णय और आदेश दिनांक 28.06.77 से।

यू.आर. ललित, वी.एन. गणपुले, वी.डी. खन्ना, ए.एम. खानविलकर, एस.के. अग्निहोत्री, सुश्री पुनम कुमारी, ए.एस. भस्मे, कृष्ण महाजन, पी.एच. पारेख, ई.आर. कुमार, सुश्री शेफाली फ़ैज़ल, वी.बी. जोशी और एम.एन. श्राफ उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति के. रामास्वामी द्वारा पारित किया गया।

अपीलों का यह समूह कानून का सामान्य प्रश्न उठाता है, हालाँकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अलग-अलग निर्णयों द्वारा कई अपीलों का निस्तारण किया था इस आधार पर उन्हें एक साथ टैग किया गया है और तीन जजों की बेंच को भेजा गया है। हम उन्हें समान निर्णय द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करते हैं। सिविल अपील संख्या 32/80 के तथ्य कानून के प्रश्न का निर्णय करने के लिए पर्याप्त हैं। एक बापू अन्ना पाटिल (संक्षेप में बी.ए. पाटिल), अन्ना साहेब के पिता, प्रथम अपीलकर्ता/प्रथम वादी और बलवंत उर्फ बालासाहेब, प्रथम प्रतिवादी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोल्हापुर, की फाइल पर विशेष सिविल सूट संख्या 79/67 में मृत प्रथम प्रतिवादी मृतक प्रथम प्रतिवादी की मृत्यु 31 अक्टूबर, 1956 को हुई। बलवंत उनके और अन्ना साहेब के संयुक्त परिवार में सबसे बड़े पुरुष सदस्य थे। उनकी बहन चौथी प्रतिवादी लक्ष्मीबाई हैं। अब यह एक स्वीकृत तथ्य है कि रूकाडी गांव में स्थित आर.एस. नं. 359 और 172/8 वाली कृषि भूमि की दो वस्तुओं को छोड़कर, कुल 15 एकड़ और 20 गुंठा की अन्य सभी संपत्तियाँ पटेल वतन से जुड़ी हुई थी को माप और सीमाओ द्वारा विभाजित किया गया था। ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार, पटेल के कार्यालय से जुड़ी वतन संपत्तियाँ अविभाज्य हो गईं। महाराष्ट्र राजस्व पटेल (कार्यालय का उन्मूलन) अधिनियम, 1962 (संक्षेप में 'अधिनियम') 1 जनवरी, 196 को लागू हुआ था। पटेल वतन की धारा 3 के प्रचालन से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद, परिवार के सबसे बड़े सदस्य होने के

नाते, बलवंत ने अधिनियम की धारा 5 के तहत पुनः अनुदान प्राप्त किया। अपीलकर्ताओं ने विभाजन और उसमें आधे हिस्से के आवंटन के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया और 15 एकड़ और 20 गुंठा को समान भागों में विभाजित करने के लिए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की। प्रथम अपील संख्या 162/69 में निर्णय और डिक्री दिनांक 28 जून, 1977 द्वारा, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कलगोंडा बबगोंडा बनाम बालगोंडा कलगोंडा, 78 बॉम्बे एल.आर. 720 में अपने पहले के फैसले का पालन करते हुए अपील स्वीकार की और डिक्री को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम के तहत पुनः अनुदान के बाद, संपत्तियाँ बलवंत की निजी संपत्ति बन गईं और इसलिए, वे विभाजन योग्य नहीं थीं।

धारा 2(ई) 'पटेल वतन' को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है मौजूदा वतन कानून के तहत वंशानुगत रूप से धारित गांव के पटेल का पद, साथ में वतन संपत्ति का कार्यकाल, यदि कोई हो, और उससे जुड़े अधिकार, विशेषाधिकार और देनदारियां। धारा 2(डी) के तहत परिभाषित 'मौजूदा वतन कानून' का अर्थ है, किसी भी क्षेत्र के संबंध में, कोई अधिनियम, अध्यादेश, नियम, उप कानून, विनियमन, आदेश, अधिसूचना, वैट-हुकुम या कोई लेखपत्र, या कोई प्रथा या पटेल वतन से संबंधित कानून का बल रखने वाली परिपाटी, और जो नियत दिन से ठीक पहले उस क्षेत्र

में लागू है। नियत दिन को धारा 2(1)(ए) के तहत अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में परिभाषित किया गया है। 'प्रतिनिधि वतनदार' को धारा (i) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ मौजूदा वतन कानून के तहत पंजीकृत या मान्यता प्राप्त वतनदार है, जिसे किसी गांव के पटेल के वंशानुगत कार्यालय के कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है।'वतनदार', जिसे (के) में परिभाषित किया गया है, का अर्थ है मौजूदा वतन कानून के तहत किसी गांव के पटेल वतन में वंशानुगत हित रखने वाला व्यक्ति, बशर्ते, कि जहां किसी भी वतन को मौजूदा वतन कानून के तहत रिकॉर्ड के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो। वतनदारों के पूरे निकाय द्वारा धारित ऐसे पूरे निकाय को वतनदार माना जाएगा। 'वतन भूमि' को धारा 2(1)(1) के तहत वतन संपत्ति का हिस्सा बनने वाली भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। 'वतन संपत्ति' को धारा 2(1)(एम) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें वंशानुगत एक गांव के पटेल कार्यालय से संबंधित कर्तव्य निष्पादन के लिए पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए मौजूदा वतन कानून के तहत रखी, अर्जित या सौंपी चल और अचल संपत्ति और राज्य सरकार द्वारा स्वेच्छा से किया गया नकद भुगतान शामिल है और जो समय-समय पर संशोधन या वापसी के अधीन है। धारा 3 नियत दिन से किसी भी परिपाटी, प्रथा, बंदोबस्त, अनुदान, समझौते, या सनद, या किसी अदालत के किसी डिक्री या आदेश, या मौजूदा वतन कानून में कुछ भी होने के बावजूद, वतन को समाप्त कर देती है।

(ए) सभी पटेल वतन एत्तद्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे;

(बी) उक्त वतन से संबंधित सभी घटनाएं (पद धारण करने का अधिकार और वतन संपत्ति और सेवा प्रदान करने का दायित्व सहित) एतद्द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी;

(सी) धारा 5, 6 और 9 के प्रावधानों के अधीन, सभी वतन भूमि एतद्द्वारा फिर से शुरू की जाएगी और तदनुसार संबंधित संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत भू-राजस्व के भुगतान के अधीन होगी, यह मानते हुए कि वह असिंचित भूमि है। परंतुक इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसलिए छोड़ दिया गया।

धारा 4 के तहत, कलेक्टर को प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने और जांच करने के बाद पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेना होगा। प्रश्न पर उनका निर्णय, राज्य सरकार की अपील पर निर्णय के अधीन, अंतिम होगा। धारा 5 की उपधारा (1) में परिकल्पना की गई है कि धारा 3 के तहत फिर से शुरू की गई वतन भूमि, एक आवेदन पर (धारा 6 और 9 के अंतर्गत नहीं आने वाले मामलों में), उस वतन के वतनदार को वापस दी जाएगी, जिससे वह संबंधित है। ऐसी भूमि के पूर्ण मूल्यांकन की राशि के बारह गुना के बराबर अधिभोग मूल्य का राज्य सरकार को वतनदार द्वारा या उसकी ओर से निर्धारित अवधि के भीतर और निर्धारित तरीके से भुगतान करने

पर और वतनदार ऐसी भूमि के संबंध में राजस्व संहिता के अनुसार एक अधिभोगी होगा, और मुख्य रूप से राज्य सरकार को भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार। परंतुक इस मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं है। इसलिए छोड़ दिया गया।

धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत, धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत अधिभोग के लिए दी गई भूमि का माप आैर सीमा के अनुसार हस्तांतरण या विभाजन के लिए कलेक्टर की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। अन्य प्रावधान इस मामले के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए छोड़ दिया गया। किसी भी उपयोग, प्रथा, परिपाटी, अनुदान, समझौते या सनद में, या अदालत के किसी डिक्री या आदेश में, या मौजूदा वतन कानून में, 1 जनवरी 1963 से प्रभावी होने के बावजूद धारा 5 सपठित धारा 3 के प्रचालन से, न केवल पटेल वतन को समाप्त कर दिया गया है, बल्कि उक्त वतन से संबंधित सभी घटनाएं, जिनमें कार्यालय और वतन संपत्ति रखने का अधिकार और सेवा प्रदान करने के लिए वतनदार का दायित्व शामिल है, समाप्त कर दी जाएंगी। धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत, धारा 3 के तहत फिर से शुरू की गई भूमि उस वतन के वतनदार को, जिससे वह जुड़ी हुई है, राज्य सरकार को वतन की ओर से उसमें उल्लेखित अधिभोग मूल्य का भुगतान करने पर वापस कर दी जाएगी।

इसके बाद वतनदार संहिता के प्रयोजन के लिए एक अधिभोगी होगा और मुख्य रूप से राज्य सरकार को भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। संहिता की धारा 5(1) के तहत दी गई भूमि के कब्जे का कोई भी हस्तांतरण या विभाजन केवल कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के साथ और धारा 5 की उप-धारा (3) में निहित शर्तों के अधीन होगा।

इसलिए, सवाल यह है कि क्या धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत किए गए पुनर्ग्रहण पर जुड़ी वतन भूमि ने वतनदार बलवंत की स्व-अर्जित संपत्ति का स्वरूप ग्रहण कर लिया है? वतनदारों की अपीलों के समूह में दलीलों का नेतृत्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ललित द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 1965 में बलवंत के पक्ष में किए गए पटेल वतन और पुनर्ग्रहण के उन्मूलन के बाद, वतन के उन्मूलन के परिणामस्वरूप, और कार्यालय से जुड़ा सेवा का भार, भूमि से जुड़े पहले से मौजूद अधिकार और देनदारियां समाप्त कर दी गईं; पुनर्ग्रहण आैर उसमें निहित शर्तें पार्टियों के अधिकारों का निर्धारण करती हैं। चूंकि यह वतनदार के लिए व्यक्तिगत रूप से किया गया पुनर्ग्रहण था, इसलिए संपत्ति उसकी स्व-अर्जित संपत्ति बन गई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद, यह सनद के संदर्भ में स्व-अर्जित संपत्ति बन गई और बलवंत भूमि राजस्व के भुगतान के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार था। इसलिए, संपत्ति बलवंत की निजी संपत्ति है। जिला कोल्हापुर वतनदारी

अधिकारों की एक विशिष्ट विशेषता रखता है और इसलिए, अनुदान से वतन के अस्तित्व का पता लगाना आवश्यक है न कि इसे अधिनियम की धारा 3 के प्रचालन के अधीन करना। 1956 में बीए पाटिल की मृत्यु हो गई, उनके निधन पर ज्येष्ठाधिकार कानून के तहत उत्तराधिकार का अधिकार खुल गया। प्रथा के अनुसार, परिवार के कनिष्ठ सदस्य को संपत्ति में किसी भी हिस्से का अधिकार नहीं है। वर्ष 1956 में संपत्ति बलवंत में निहित हो गई और केवल उसके उत्तराधिकारी ही बलवंत की संपत्ति के उत्तराधिकार के हकदार हैं। इसलिए, अपीलकर्ताओं को संपत्ति में किसी भी विभाजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें विवाद में कोई ताकत नहीं दिखती है। उठाए गए प्रश्न अब रेस-इंटिग्रा नहीं रह गए हैं। ज्येष्ठाधिकार पहले जन्म और संपत्ति में सफल होने के लिए उम्र में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति के अधिमान्य अधिकारों को दर्शाता है, क्योंकि उम्र में सबसे वरिष्ठ अपने छोटे भाई को प्राथमिकता देते हुए संपत्ति में सफल होने का हकदार है। एक अविभाज्य संपत्ति में, हालांकि अन्य अधिकार जो एक सहदायिक को संयुक्त परिवार की संपत्ति में जन्म से प्राप्त होते हैं, मौजूद नहीं हैं, वरिष्ठ सदस्य के जन्म से जीवित रहने का अधिकार अभी भी बना हुआ है। यह स्थापित करने के लिए कि मिताक्षरा द्वारा शासित एक परिवार, जिसमें एक अविभाज्य संपत्ति है, संयुक्त रूप से समाप्त हो गया है, परिवार के कनिष्ठ सदस्यों की ओर से उत्तराधिकार के अधिकार को त्यागने के व्यक्त या निहित इरादे को साबित करना आवश्यक है।

संपत्ति के लिए केवल भोजन और निवास में अलगाव दिखाना पर्याप्त नहीं है। प्रथा या विशेष कानून हिंदू संयुक्त परिवार के जीवित रहने से उत्तराधिकार के नियम को विस्थापित करता है।

दत्तात्रेय एवं अन्य बनाम कृष्णा राव एवं अन्य, 1993 (1) एससीसी 32 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हम में से एक (के. रामास्वामी, जे.) सदस्य थे, को ज्येष्ठाधिकार के नियम पर व्यापक रूप से विचार कर ना था और पेज 39 पर माना गया था कि ऐसी संपत्तियां हैं जो विशेष कानून या रीति- रिवाज के तहत परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य, आम तौर पर सबसे बड़े सदस्य को मिलती हैं, अन्य सदस्यों को छोड़कर, और जो कानून की नजर में संयुक्त परिवार की संपत्ति होने के बावजूद अविभाज्य है, यद्यपि वे कानून की नजर में संयुक्त परिवार एवं अन्य सदस्यों की समान रूप से संपत्ति है; उनके अधिकार कई प्रतिबंधों या सीमाओं से बाधित हैं। पृष्ठ 42 पैरा 18 में यह भी कहा गया कि अविभाज्य संपत्ति, हालांकि ज्येष्ठाधिकार और उत्तरजीविता के नियम से परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य पर आती है, यह भी साबित किया जाना चाहिए कि कनिष्ठ सदस्यों ने स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से उसमें अपने हिस्से के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया है। एक अविभाज्य संपत्ति अनुदान या कस्टम द्वारा बनाई जा सकती है। यह रूढ़ि का सृजित प्राणी है। सामान्य संयुक्त पारिवारिक की संपत्ति के मामले में

परिवार के सदस्यों को विभाजन का अधिकार और उत्तरजीविता का अधिकार है। अविभाज्य संपत्ति के मामले में विभाजन का अधिकार मौजूद नहीं हो सकता। पहले से मौजूद कानून में वतनदार द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अनुदान आदि द्वारा चल या अचल संपत्ति को वतन से जोड़ दिया जाता था। जैसा कि इसके सहवर्ती ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को मान्यता दी और इसके प्रचालन से, परिवार में सबसे बड़े पुरुष सदस्य या पहली शाखा में सबसे बड़े को वतन का अधिकार मिलता है और वतन से जुड़ी संपत्ति का उपभोग वतन सेवा प्रदान करने के परिणाम के रूप में या परिणामी रूप में लिया जाएगा। क़ानून ज्येष्ठाधिकार नियम द्वारा वतन संपत्ति के रिवाज और उत्तराधिकार के प्रचालन को भी निरस्त कर सकता है और अधिनियम ने वास्तव में उस उद्देश्य को प्राप्त किया, वतन के कार्यालय और सेवा के भार सहित इससे जुड़ी देनदारियों को समाप्त कर दिया और भूमि को रैयतवारी भूमि बना दिया। पुनर्ग्रहण पर तत्कालीन वतनदार भूमि को संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में और संयुक्त परिवार की ओर से भूमि रखता है।

इस न्यायालय ने नागेश बिस्टो देसाई आदि बनाम खांडो तिर्मल देसाई आदि (1982] 3 एससीआर 341, में बॉम्बे मर्ज्ड टेरिटरीज मिस्लेनियस अलाईनेशन एबोलिशन एक्ट 1955 के प्रभाव पर विचार किया, जो कि पूर्व-मौजूदा ज्येष्ठाधिकार नियम है, उस अधिनियम के तहत

उन्मूलन के परिणाम और उसके परिणामी प्रभाव पर। इसमें यह भी तर्क दिया गया था कि कुंडगोल देशगत एस्टेट एक अविभाज्य संपत्ति थी और जो सन् 1955 के अधिनियम 22 के तहत वतन के उन्मूलन के परिणामस्वरूप वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा शासित होता था। उसमें विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या पारिवारिक रीति-रिवाज या स्थानीय रीति-रिवाज के कारण वंशानुगत जिला (परगना) कार्यालय से संबंधित परगना वतन की अविभाज्य भूमि ने संयुक्त परिवार की होने का स्वरूप खो दिया है उस अधिनियम की धारा 4 के तहत वतन की बहाली और उसके प्रतिग्राही और क्या वतनदार के रूप में उसकी स्थिति के कारण भूमि वतनदार की अनन्य थी और क्या वे विभाजन के लिए सक्षम नहीं थे।

तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद माना था कि परिवार के सबसे बड़े सदस्य को वतन देने से वतन संपत्ति उस व्यक्ति की अनन्य संपत्ति नहीं बन जाती है जो फिलहाल वतनदार है। हालांकि संपत्ति अविभाज्य है लेकिन वह संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति हो सकती है। संपत्ति की अविभाज्यता संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में इसकी प्रकृति को नष्ट नहीं करती है या इसे अंतिम धारक की पृथक संपत्ति का रूप प्रदान नहीं करती है, जिससे उत्तरजीविता का अधिकार नष्ट हो जावे; इसलिए संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति के

अपने स्वरूप को बनाए रखती है और सामान्य कानून द्वारा उस व्यक्ति को हस्तांतरित होती है जो वास्तव में और कानून के अनुसार संपत्ति के संबंध में संयुक्त है। वह वरिष्ठ पंक्ति में वरिष्ठ सदस्य भी हैं। अविभाज्यता रीति-रिवाज का एक आवश्यक सृजन है। सामान्य संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के मामले में, हस्तांतरण ऐसी संपत्ति पर लागू सामान्य मिताक्षरा कानून द्वारा शासित होता है। यद्यपि संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक को जन्म से मिलने वाले अन्य अधिकार अब मौजूद नहीं हैं, उत्तरजीविता पर वरिष्ठ नागरिक का अधिकार अभी भी बना हुआ है। यह स्थापित करने के लिए कि मिताक्षरा द्वारा शासित एक परिवार जिसमें पैतृक अविभाज्य संपत्ति है, संयुक्त नहीं रह गया है, परिवार के कनिष्ठ सदस्यों की ओर से उन्हें त्यागने का इरादा, व्यक्त या निहित, साबित करना आवश्यक है। हालांकि संपत्ति अविभाज्य है, लेकिन यह धारक की अलग और विशिष्ट संपत्ति नहीं है, जहां संपत्ति पैतृक है और धारक इसका उत्तराधिकारी है, यह अविभाजित परिवार की संयुक्त संपत्ति का हिस्सा होगा। संयुक्त परिवार की संपत्ति के वृतांत जो अभी भी संयुक्त परिवार की संपत्ति से जुड़े हैं, उत्तरजीविता का अधिकार है, जो निश्चित रूप से अविभाज्यता की प्रथा से असंगत नहीं है। संयुक्त परिवार के कनिष्ठ सदस्य, अविभाज्य संयुक्त परिवार की संपत्ति के मामले में, जन्म से संपत्ति में कोई अधिकार नहीं लेते हैं और इसलिए, संपत्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कि यह अविभाज्य है और विभाजन का कोई

अधिकार नहीं है। उसी वतन के वतनदार में वतनदार के अलावा संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जो वतन संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने और उसका उपभोग करने के हकदार थे। वतन भूमि का धारक अपृथक भूमि के रूप में अधिभोग अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का हकदार है। वतन का उन्मूलन कार्यालय को समाप्त कर देता है और उस अधिकार को संशोधित करता है जिसमें भूमि रखी गई है।

1955 अधिनियम की धारा 3 के संचालन से उत्पन्न उन्मूलन, विलुप्त होने और संशोधन को राज्य सरकार द्वारा जब्ती या बहाली की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग से नहीं माना गया था। वतन भूमि की सेवा का रूपान्तरण जिसके द्वारा वतनदारों को भू-राजस्व के भुगतान के संबंध में अपने कार्यालयों से जुड़ी सेवाओं को निष्पादित करने के दायित्व से हमेशा के लिए राहत मिल गई थी। संपत्ति के उत्तराधिकार को विनियमित करने वाला वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार अधिनियम 1955 की धारा 4 के तहत लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि यह वतन के वृतांत से अधिक कुछ नहीं है और जो उस अधिनियम की धारा 4 द्वारा निरस्त कर दी गई है। यह माना गया कि यदि वतन परिवारों का वतन संपत्ति में वंशानुगत हित है, तो ऐसी विरासत से परिवार के सभी सदस्यों को लाभ होता है क्योंकि संपत्ति परिवार और वतन परिवार से संबंधित सभी व्यक्तियों, जिनके पास वंशानुगत हिस्सेदारी है की होती है। ऐसी वतन संपत्ति में रुचि रखने वाले

वतन अधिनियम के तहत 'उसी वतन के वतनदार' कहलाने के हकदार थे। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को कुछ समय के लिए वतनदार के साथ-साथ वतन भूमि का धारक माना जाना चाहिए और इसलिए उस अधिनियम की धारा 4 के तहत वतनदार को भूमि का पुनः अनुदार पूरे संयुक्त हिन्दू परिवार के लाभ को सुनिश्चित करना चाहिए। इस न्यायालय ने लक्ष्मीबाई सदाशिव डेट बनाम गणेश शंकर डेट, 79- बाॅम्बे एल.आर.234 में रिपोर्ट किए गए बॉम्बे हाईकार्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय व अन्य निर्णय धोंडी विठोबा बनाम महादेव **दगडू, 75 बाम्बे एल.आर**. 290 **को बरकरार रखा। बबगोंडा मामले में डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज कर दिया गया।**

वही रेश्यो स्वतंत्र रूप से इस मामले में भी तथ्यों पर लागू होगा यह देखा गया है कि धारा 3 के प्रचालन से वतन को समाप्त कर दिया गया है और वतनदारी से जुड़े सभी वृतांत जिसमें पहले से मौजूद प्रथा, कानून का प्रचालन या न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश को वैधानिक प्रचालन द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार वतन से जुड़े वृतांत यानी पटेल के रूप में सेवा प्रदान करने का दायित्व विलुप्त हो गया और भूमि रैयतवारी भूमि बन गई, वतन का कार्यालय समाप्त हो गया, वंशानुगत जेष्ठाधिकार समाप्त हो गया आैर पुनर्ग्रहण पर भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की संपत्ति बन गई जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के लिए और उनकी ओर से

वतनदार के पास थी परिवार के सभी सदस्य उत्तरजीविता पर विभाजन का दावा करने के हकदार बन गये। यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद 1 जनवरी, 1963 को लागू हुआ था इसलिए 1956 में पिता की मृत्यु के बाद और मौजूदा वतन कानून के अनुसार वतनदार के रूप में उत्तराधिकार का अधिकार वरिष्ठ वंशानुगत पुरुष वंशज यानी बलवंत के लिए खुल गया। पुनर्ग्रहण 1965 में बनाया गया था, जिस वर्ष परिवार के सभी सदस्यों को विभाजन का दावा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार, अन्ना साहब, वादी नंबर 1 अपने भाई बलवंत के साथ 15 एकड़ 20 गुंठा में 1/2 हिस्सेदारी का दावा करने के हकदार बन गए। कलगोंडा बबगोंडा पाटिल बनाम बालगोंडा कलगोंडा पाटिल और अन्य, 1989 (1) एससीसी 246 में इस न्यायालय की एक पीठ ने नागेश बी. देसाई के मामले के रेश्यो का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले को उलट दिया। यह मामला कोल्हापुर राज्य द्वारा वाट-हुकुम की पटेल वतन संपत्ति से संबंधित है। अनंत किबे बनाम पुरूषोत्तम राव, एआईआर 1984 एससी 1121 में, तीन न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ ने एम.पी. रिजवर्ड (इनाम भूमि) और एम.पी. लैंड रिवेन्यू कोड के तहत हस्तांतरण के एक विशेष तरीके के रूप में संपत्ति के ज्येष्ठाधिकार और अविभाज्यता के नियम के प्रभाव पर विचार किया और यह माना गया कि इनाम भूमि, इनाम की आय से अर्जित संपत्तियों के साथ-साथ पैतृक संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, हालांकि अविभाज्य संपत्ति

जो इनाम भूमि समाप्त होने के बाद वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित की गई और इनाम भूमि समाप्त होने के बाद संयुक्त संपत्ति बन गई फलस्वरूप यह विभाजनकारी हो गया। वादी को उन संपत्तियों में अपने आधे हिस्से की सीमा तक विभाजन और अलग कब्जे का हकदार माना गया। हमें निर्णय के लिए मामले को पांच न्यायाधीशों के पास भेजने का कोई आधार नहीं मिला। शिवप्पा तम्मनप्पा करबन बनाम पारसप्पा एच. कुरबन और अन्य, 1994 (4) स्केल 750, के मामले में दो न्यायाधीशों (के. रामास्वामी और एन. वेंकटचला, जे.जे.) की एक पीठ ने नागेश बी. देशाई और नालगोंडा के निर्णयों का अनुसरण करते हुए कर्नाटक ग्राम अधिकारी उन्मूलन अधिनियम 1961 के प्रचालन में आने के बाद कनिष्ठ सदस्यों द्वारा विभाजन के अधिकार को बरकरार रखा। शिद्दप्पा सतप्पा मुरुगुडे और अन्य बनाम रामप्पा एस मुरुगुडे और अन्य, सीए नंबर 944 ऑफ 1973 में निर्णय दि. 25 नवंबर, 1986 में दो जजों की बेंच ने माना कि यह संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है, बल्कि वतनदार की अलग संपत्ति है। तीन न्यायाधीशों की दो पीठों द्वारा तय किए गए नागेश बी.देसाई का मामला और आनंद किबे का मामला पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया इसलिए, उचित सम्मान के साथ, उसके रेश्यो को अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है। बंडू कल्लप्पा पाटिल और अन्य बनाम बालागोंडा एस. पाटिल, 1971 (1) एससीजे 429 का रेश्यो इस मामले के तथ्यों पर समान रूप से लागू नहीं है। उस मामले में प्रश्न

उन्मूलन से पहले, पहले से मौजूद कानून के तहत था और इसलिए, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने माना कि वाट-हुकुम वतन भूमि के परिवार को नतमस्क का रूप में प्रदान करता है।

निस्संदेह, वाट हुकुम के प्रचालन से, उत्तराधिकार की जांच की गई और मृतक वतनदार के सबसे बड़े बेटे को उसका उत्तराधिकारी (नवावाला) घोषित किया गया, और वह विरासत द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में कार्यालय से जुड़ी वतन संपत्ति का उत्तराधिकारी बना। यह कि पहले से मौजूद कानून, प्रथागत या संहिताबद्ध, का संचालन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के संचालन के अधीन होगा और (तत्कालीन) कोलापुर राज्य में प्रचलित असंगत कानून निरस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले माना गया था, वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को तब तक बाहर रखा गया जब तक कि वतन और सेवा का भार समाप्त नहीं हो गया। पुनर्ग्रहण के बाद, संपत्ति सहदायिक हो जाती है और सहदायिकों के बीच विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है। इसलिए, यह तर्क कि कोलापुर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1920 के प्रावधान लागू हो गए हैं और अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से पहले की गई व्याख्या की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक डिक्री सही दी और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस फैसले का पालन करने में कानून की स्पष्ट त्रुटि की थी, जिसे बाद में इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है, ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल किया जाता है और अपीलीय अदालत का फैसला रद्द किया जाता है।

सिविल अपील क्रमांक 2267/80

उपरोक्त अपीलों में हमारे निर्णय का रेश्यो इस मामले में तथ्यों पर समान रूप से लागू होगा। हालाँकि, इस अपील में उठाया गया एक और तर्क यह है कि प्रतिवादियों ने नुस्खे द्वारा स्वामित्व हासिल कर लिया है। यह दलील दी गई थी कि उत्परिवर्तन 16 अगस्त, 1955 को प्रभावी हुआ था और उस तारीख से, यह कहा गया था, प्रतिवादी अनन्य कब्जे और उपभोग में थे और विलय के बाद विलय किए गए क्षेत्र विविध अलगाव उन्मूलन अधिनियम, 1955 के तहत वतन के उन्मूलन के बाद, यह यह उनकी अनन्य संपत्ति थी और इसलिए, उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व निर्धारित किया। उस विवाद को अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अस्वीकृत्त कर दिया।

परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि अचल संपत्ति या स्वामित्व के आधार पर उसमें किसी भी हित के कब्जे के लिए, 12 वर्ष की सीमा उस तारीख से लागू होती है जब

प्रतिवादी का हित वादी के प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल कब्ज़ा का अर्थ है एक शत्रुतापूर्ण दावा अर्थात ऐसा कब्ज़ा जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वास्तविक मालिक के स्वामित्व से इनकार करता है। अनुच्छेद 65 के तहत, प्रतिवादियों पर सकारात्मक साबित करने का भार है। एक व्यक्ति जो अपने स्वामित्व को प्रतिकूल कब्जे पर आधारित करता है, उसे स्पष्ट और सुस्पष्ट साक्ष्य द्वारा यह दिखाना होगा कि कब्जा वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण था और दावा की गई संपत्ति पर उसके स्वामित्व से इनकार के समान था। यह तय करने में कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा कथित कृत्य प्रतिकूल कब्जे का गठन करते हैं, उन कृत्यों को करने वाले व्यक्ति की शत्रुता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसलिए, जो व्यक्ति अपने स्वामित्व को प्रतिकूल कब्जे पर आधारित करता है, उसे स्पष्ट और सुस्पष्ट साक्ष्य के साथ यह दिखाना होगा कि कब्जा वास्तविक मालिक के प्रति शत्रुतापूर्ण था और दावा की गई संपत्ति पर उसके स्वामित्व से इनकार के समान था।

जहां कब्जे को वैध स्वामित्व के लिए संदर्भित किया जा सकता है, वहां इसे प्रतिकूल नहीं माना जाएगा, इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति का कब्जा वैध हक के लिए संदर्भित किया जा सकता है, उसे यह दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि उसका कब्जा दूसरे के स्वामित्व के प्रति

शत्रुतापूर्ण था। जो व्यक्ति दूसरे की ओर से कब्ज़ा रखता है, वह केवल उस दूसरे के स्वामित्व से इनकार करके अपने कब्जे को प्रतिकूल नहीं बनाता है ताकि वह खुद को परिसीमा क़ानून का लाभ दे सके। इसलिए, जो व्यक्ति वैध स्वामित्व के साथ कब्ज़ा करता है, वह यह दिखावा करके कि उसके पास कोई स्वामीत्व नहीं है, वह उस स्वामीत्व से दूसरो को वंचित नहीं कर सकता है।

हिंदू संयुक्त परिवार के मामले में, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के बीच हितों का समुदाय और कब्जे की एकता है और प्रत्येक सहदायिक, सहदायिक संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व और उपभोग का हकदार है। केवल इस तथ्य का कि सहदायिकों में से एक के पास संयुक्त कब्ज़ा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बेदखल कर दिया गया है। परिवार के किसी सदस्य द्वारा पारिवारिक संपत्ति पर कब्ज़ा अन्य सदस्यों के प्रतिकूल नहीं हो सकता है, बल्कि उसे स्वयं और अन्य सदस्यों की ओर से माना जाना चाहिए। इसलिए, एक का कब्ज़ा सभी का कब्ज़ा है। प्रतिकूल कब्ज़ा स्थापित करने वाले सदस्य पर अपने कब्जे के प्रतिकूल स्वरूप को सकारात्मक रूप से साबित करने का भारी बोझ होता है कि अन्य सदस्यों की जानकारी में उसने अपने अनन्य स्वामित्व का दावा किया है और अन्य सदस्यों को संपत्ति का उपभोग लेने से पूरी तरह से बाहर रखा गया है और इस तरह का प्रतिकूल कब्ज़ा वैधानिक अवधि तक जारी रहा। लगान

और राजस्व की वसूली के लिए परिवार के बड़े भाई के नाम पर नामांतरण दूसरे के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्य साबित नहीं होता है। वर्तमान मामले में, विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने का वादी का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उत्पन्न हुआ था और कलेक्टर द्वारा धारा धारा 5(1) के तहत पुनः अनुदान दिया गया था। इसलिए, प्रतिवादी को अभिवचन करना होगा और साबित करना होगा कि पुन: अनुदान के बाद, उसने वाद की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति पर अपना अनन्य अधिकार, हक और हित का दावा किया और वादी ने अधिकार के ऐसे शत्रुतापूर्ण उपयोग को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को 12 वर्षों की संपूर्ण वैधानिक अवधि के दौरान बिना किसी अनुमति और बाधा के उस शत्रुतापूर्ण हक के दावे में वर्णित संपत्ति का निरंतर कब्ज़ा और उपभोग लेने की अनुमति दी गई और वादी इस पर कायम रहा।

यह देखा जा सकता है कि जब तक भूमि का स्वरूप नहीं बदला जाता, तब तक वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार के नियम के प्रचालनानुसार भूमि अविभाज्य हो गई इसलिए वादी इसमें विभाजन के लिए किसी अधिकार का दावा नहीं कर सका। अधिनियम लागू होने के बाद और पुनर्ग्रहण करने पर विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ था। इस बात की कोई दलील या सबूत नहीं है कि प्रतिवादियों ने वादी की जानकारी में संपत्ति पर अपने शत्रुतापूर्ण स्वामित्व का दावा किया था और

उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। इसके अभाव में विभाजन का दावा करने का अधिकार तभी उत्पन्न होगा जब विभाजन के अधिकार से इनकार कर दिया जाएगा। अधिनियम के तहत भूमि के स्वरूप को अविभाज्यता से भाज्यता में बदल दिया गया था। इस प्रकार, दोनों अदालतों ने सही माना है कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व हासिल नहीं किया है। तदनुसार यह अपील भी खारिज की जाती है।

सिविल अपील क्रमांक 2485/85

इस मामले में मुख्य प्रश्न के अलावा जो पहले से ही अपीलकर्ताओं के खिलाफ तय किया गया था, दो और विवाद उच्च न्यायालय में उठाए गए थे। उन्होंने पुनर्विभाजन के लिए कुछ अन्य भूमि को शामिल करने के लिए जवाब दावे में संशोधन के लिए आदेश 6 नियम 17 के तहत उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। खामियों के आधार पर संशोधन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इस अपील में भी यही बात दोहराई गई। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमें नहीं लगता कि यह इस न्यायालय द्वारा इतने समय में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाला एक उपयुक्त मामला है। यह भी अभिवचन किया गया कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था। उनका मामला यह है कि विभाजन 1955 के अधिनियम 22 के लागू होने से पहले हुआ था, वे मालिक के रूप में कब्जे में रहे और इसलिए, मुकदमा परिसीमा से वर्जित है। अपीलीय

अदालत ने पूर्व विभाजन पर अविश्वास किया। इसे भी उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मुकदमा भूमि की प्रकृति को अविभाज्यता से भाज्यता में बदलने के बाद दायर किया गया था और इसलिए, यह परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को उचित पाते है। उच्च न्यायालय और अपीलीय अदालत ने साक्ष्यों का सही मुल्यांकन किया है और निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इसलिए, यह न्यायालय साक्ष्य का मुल्यांकन नहीं करता है। अपील को सी ए 32/80 के साथ भी टैग किया गया है, विवाद और कानून का प्रश्न यहां पहले दिए गए निर्णय से समाप्त हो गया है। अपीलीय अदालत ने मामले को पुनर्विचार के लिए भेज दिया कि क्या पहले अपीलकर्ता द्वारा अपीलार्थी सं. 2 से 8 और प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया गया हस्तांतरण कानूनी आवश्यकता के लिए था। जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। इसलिए, उपरोक्त के अधीन, उच्च न्यायालय और अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है। तद्नुसार अपील खारिज की जाती है। सिविल अपील क्रमांक 3200-01/91 उठाया गया एकमात्र प्रश्न भूमि के स्वरूप और विभाजन के अधिकार के संबंध में था। चूँकि अपीलों को सी ए 32/80 के साथ टैग किया गया था, विवाद सी ए 32/80 में तय किए गए कानून के प्रश्न के साथ समाप्त हो जाता है, इसलिए, अपीलें भी खारिज की जाती हैं।

सिविल अपील संख्या 2557/93

उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील संख्या 1277/73 में, सनद की शर्तों की व्यख्या करते हुए, यह माना कि 1955 के अधिनियम 22 में वतनदार के लाभ के लिए यह एक निजी संपत्ति है। संपत्ति ने स्व-अर्जित संपत्ति का स्वरूप ग्रहण किया और इसलिए, संपत्तियां विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के फैसले को उलट दिया गया। कानून के प्रश्न पर, अपील को सी ए 32/80 के साथ टैग किया गया था। उन्हीं कारणों से उसमें दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह अपील भी स्वीकार की जाती है। आगे यह तर्क कि दस्तावेज़ों की व्याख्या में शामिल विविध इतिहास का पता लगाने के लिए उन पर गौर करना आवश्यक है, अस्थिर है क्योंकि अपील को डी-टैग करने का सवाल ही नहीं उठता। सनद Ex.70 और 71 की शर्तें और नीचे की अदालतों के फैसले को उलटने में उच्च न्यायालय द्वारा उन पर की गई व्याख्या मुख्य रूप से 1955 के अधिनियम 22 के प्रावधानों की व्याख्या पर निर्भर करती है जो इस न्यायालय द्वारा पहले ही तय कर दी गई थी। उच्च न्यायालय को अपनी पूर्ण पीठ के निर्णय और इस न्यायालय के निर्णय का लाभ नहीं मिला जिसके कारण उच्च न्यायालय ने गलत दृष्टिकोण अपनाया। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। सी ए No.32/80 (पूर्व) में बताए गए कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है और

दूसरी अपील संख्या 1177/73 में उच्च न्यायालय द्वारा दि. 7 नवंबर, 1981 के फैसले और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट के फैसले और अपीलीय अदालत के फैसले बहाल रहेगें।

तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों को इन सभी अपीलों में अपना-अपना खर्चा वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

नोटः यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेश पुनेठा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।